उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

2013 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 291

सोम प्रकाश डबराल .....संशोधनवादी

बनाम

उत्तराखंड राज्य .....प्रतिवादी

वर्तमान: श्री बी.एम. पिंगल, अधिवक्ता, संशोधनवादी के लिए।
श्री सुभाष त्यागी भारद्वाज, उप. सुश्री शिवानी गंगवार के साथ एजी,
राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

यह आपराधिक पुनरीक्षण 2009 के आपराधिक मामले संख्या 449 "राज्य बनाम सोम प्रकाश" में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.11.2009 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त ने आईपीसी की धारा 408 के तहत दोषी ठहराया गया , और आईपीसी की धारा 408 के तहत 1,000/- रुपये (केवल एक हजार रुपये) के जुर्माने के साथ दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दिनांक 20.11.2009 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल के समक्ष अपील दायर की, जिसे भी दिनांक 15.10.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

2. अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि पुनरीक्षणवादी/अभियुक्त के विरुद्ध आईपीसी की धारा 409 के अंतर्गत थाना कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुनरीक्षणवादी/अभियुक्त ने सोसायटी के खाते से धोखाधड़ी कर पैसे निकाल लिए हैं। अनुसंधान के बाद पुलिस ने पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में समर्पित किया।

3. अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने तीन गवाहों से पूछताछ की। PW1 सते सिंह चौहान, PW2 रमेश चंद्र बिडला और PW3 SI श्री एमएमएस बिष्ट से पूछताछ की गई। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पुनरीक्षणकर्ता के बयान दर्ज किए गए। जवाब में उन्होंने अभियोजन की कहानी से इनकार किया.

4. रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों की सराहना करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता को आईपीसी की धारा 408 के तहत दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई। व्यथित महसूस करते हुए, संशोधनवादी ने अपील को प्राथमिकता दी। अपीलीय अदालत ने पुनरीक्षणकर्ता का पक्ष नहीं लिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

5. संशोधनवादी के विद्वान वकील श्री बीएम पिंगल अपने तर्क को केवल सजा की मात्रा तक ही सीमित रखेंगे। उनका कहना था कि यह घटना वर्ष 1993 की है। तब से लगभग 27 वर्ष बीत चुके हैं और संशोधनवादी को अपने खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के कारण लगातार मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि सजा को कम करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। हालाँकि, उनका कहना था कि यदि अदालत को वांछनीय लगता है, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया जुर्माना बढ़ाया जा सकता है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

7. रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य की दोबारा सराहना करने और पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों पर विचार करने के बाद, मुझे नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और आदेशों में कोई अवैधता या विकृति नहीं मिली। ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने उपरोक्त धारा के तहत पुनरीक्षणवादी को सही ढंग से दोषी ठहराया है। इसलिए, संशोधनवादी का दृढ़ विश्वास पुष्ट होता है। अब, इस न्यायालय को केवल सजा के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करना है।

8. सजा के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील की दलील पर विचार करने के बाद, मेरे विचार से, घटना के 27 वर्ष बीत जाने के बाद पुनरीक्षणवादी को जेल भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा,

ऐसे में सजा का हकदार है। 15,000/- रुपये के जुर्माने के साथ पहले ही पूरी हो चुकी अवधि को कम कर दिया जाएगा।

9. तदनुसार, आईपीसी की धारा 408 के तहत निचली अदालतों द्वारा दर्ज की गई सजा की पुष्टि करके संशोधन की आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है । हालाँकि, ऊपर बताए गए कारणों से, आक्षेपित आदेशों के वाक्य भाग को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि संशोधनकर्ता को सजा की अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है और साथ ही रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) जो उसे आज से एक महीने के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमा करना होगा। पुनरीक्षणकर्ता उसके द्वारा पहले ही जमा किए गए जुर्माने, यदि कोई हो, के समायोजन का हकदार होगा। ऊपर बताए अनुसार जुर्माना जमा करने में विफलता के मामले में, नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज की गई सजा पुनर्जीवित हो जाएगी।

10. संशोधनवादी जमानत पर है। जब तक किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं और जमानतदारों को मुक्त कर दिया गया है।

11. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन के लिए ट्रायल कोर्ट को तुरंत भेजी जाए। निचली अदालत का रिकार्ड भी वापस भेजा जाए।

(लोकपाल सिंह, जे.)
14.01.2021